बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

# सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 64 ● नई दिल्ली ● बुधवार 17 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

### भारतीय सेना के शौर्य और इंदिरा के साहसिक नेतृत्व की मिसाल है 1971 की विजय- कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने विजय दिवस पर मंगलवार को कहा कि 1971 के युद्ध की विजय भारतीय सेना के शौर्य और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दूरदर्शी एवं साहसिक नेतृत्व की मिसाल है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन भी किया। खरगे ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज ही के दिन 1971 में इतिहास रचा गया, जब भारत की वीर सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान को निर्णायक रूप से परास्त कर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई और विश्व के मानचित्र को नया स्वरूप दिया।''

# आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में खड़ी हुई सोनिया गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने मंगलवार को शून्यकाल के दौरान लाखों महिला फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की दुर्दशा को उजागर करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग की। गांधी ने इन सरकारी पहलों को महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बताया, लेकिन इस बात पर खेद व्यक्त किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और बाल विकास में उनके अपरिहार्य योगदान के बावजूद, कार्यकर्ता अत्यधिक बोझ, कम वेतन और कम महत्व की बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी के रूप में वर्गीकृत आशा कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान, मातृ स्वास्थ्य सहायता और परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संभालती हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के साथ कम मानदेय मिलता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के लिए केंद्रीय भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को केंद्र सरकार से कार्यकर्ताओं के लिए

लगभग 4,500 रुपये और सहायिकाओं के लिए 2,250 रुपये का मूल मानदेय मासिक रूप से मिलता है, जिसमें राज्यों द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। उन्होंने देशभर में आईसीडीएस के विभिन्न स्तरों पर लगभग 3,00,000 रिक्तियों की ओर इशारा किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों बच्चों और माताओं को आवश्यक पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। गांधी ने सेवा वितरण को प्रभावित करने वाली कर्मचारियों की कमी की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि कम वेतन के अलावा, वर्तमान में आईसीडीएस में विभिन्न स्तरों पर लगभग तीन लाख रिक्तियां हैं। इन कमियों के कारण लाखों बच्चे और माताएं आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

यहां तक कि जब ये पद भर भी दिए जाते हैं, तब भी 2011 के बाद से अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अभाव के कारण जनसंख्या के मानदंडों से कम पड़ते हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से राज्यों के सहयोग से उपायों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जिनमें सभी मौजूदा रिक्तियों को भरना, सभी कर्मचारियों को समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, इन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र सरकार के योगदान को दोगुना करना, 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना शामिल है, ताकि मौजूदा पोषण और स्वास्थ्य पहलों के अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सक्षम बनाया जा सके।

# विजय दिवस पर राष्ट्रपति भवन में भारत के वीरों को सम्मान, परमवीर दीर्घा का हुआ लोकार्पण

नई दिल्ली। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परम वीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस गैलरी में परम वीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस गैलरी का उद्देश्य आगंतुकों को हमारे उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अदम्य संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। यह उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। जिन गलियारों में अब परम वीर दीर्घा स्थापित की गई है, वहां पहले ब्रिटिश सहायक अधिकारियों के चित्र प्रदर्शित किए जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय नायकों के चित्रों को प्रदर्शित करने की यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। परम वीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता, साहस और आत्मबलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के युद्ध में भारत की निर्णायक विजय की याद दिलाता है, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। भारतीय सेना ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और शौर्य को याद किया और सूचना के अतिरिक्त महानिदेशालय द्वारा जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेश की मुक्ति की ऐतिहासिक गाथा साझा की। एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय सेना ने लिखा कि विजय दिवस केवल एक तारीख नहीं है, यह 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक और निर्णायक विजय का प्रतीक है। उन्होंने इस युद्ध को भारत के सैन्य इतिहास को नया रूप देने वाली विजय बताया और मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बीच हुए शक्तिशाली संघर्ष को याद किया, जिसने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को स्वतंत्रता की दिशा में आवश्यक गति प्रदान की।

पोस्ट में लिखा था कि यह एक ऐसी जीत थी जिसमें मुक्ति वाहिनी और भारतीय सशस्त्र बलों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, और साथ मिलकर बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष को स्वतंत्रता की ओर निर्णायक गति प्रदान की... एक ऐसी विजय जिसने भारत के सैन्य इतिहास को नया रूप दिया, दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र को जन्म दिया।

# राम का नाम बदनाम मत करो, लोकसभा में दिखा थरूर का शायराना अंदाज

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया और इसे बहुत अफसोसजनक और पीछे की ओर ले जाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है। थरूर ने सदन में बिल पेश होने का विरोध करते हुए कहा कि गांधीजी का नाम हटाने का फैसला गलत है। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार योजना की आत्मा और दार्शनिक आधार पर हमला है। उन्होंने गांधीजी के राम राय के सपने का जिक्र किया और कहा कि यह कभी सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि गांवों को सशक्त बनाने और ग्राम स्वराज पर आधारित सामाजिक-आर्थिक योजना थी। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने आगे कहा कि मनरेगा में गांधीजी का नाम रखना उनकी सोच से गहरा जुड़ाव दिखाता था। अब उनका नाम हटाना योजना से नैतिक दिशा और ऐतिहासिक वैधता छीनने जैसा है। उन्होंने बिल के नाम पर भी सवाल उठाया। नाम में दो भाषाओं का इस्तेमाल सिर्फ जी राम जी बनाने के लिए किया गया है, जो संविधान के अनुछेद 348 का उल्लंघन लगता है थरूर ने कहा कि यह सब सुनकर बचपन की एक गाना याद आ गया। फिर उन्होंने सदन में गुनगुनाया ङ्क राम का नाम बदनाम मत करो। उनके इस अंदाज से सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर विपक्षी सांसदों ने तालियां बजाईं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 पेश किया। इसे वीबी-जी राम जी बिल कहा जा रहा है। यह मनरेगा को पूरी तरह बदल देगा। बिल के मुताबिक, हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का मजदूरी वाला काम मिलेगा, जो पहले 100 दिन था। राज्यों को नए कानून आने के छह महीने के अंदर अपनी योजना बनानी होगी जो इस बिल से मेल खाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि यह बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ा आधुनिक ढांचा बनाएगा। यह योजना पानी की सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़े काम और मौसम की मार से बचाव के विशेष से जुड़े काम पर केंद्रित होगा।

# पारंपरिक बीजों पर राष्ट्रीय बीज विधेयक नहीं होगा लागू

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय बीज विधेयक 2025 किसानों और उनके पारंपरिक बीजों पर लागू नहीं होगा। कृषि एवं किसान कल्याण राय मंत्री राम नाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि इस विधेयक में किसानों के पारंपरिक अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की गई है। मंत्री ने कहा कि यह बिल किसानों को अपने खेतों में उगाए गए बीजों को उगाने, बोने, बचाने, आपस में बदलने और बेचने के अधिकार को सुरक्षित रखता है। यह प्रावधान पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के अनुरूप है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिल की शर्तें किसानों और किसान किस्मों पर लागू नहीं होंगी, जिनमें पारंपरिक और देसी बीज शामिल हैं। राम नाथ ठाकुर ने बताया कि इस विधेयक का मसौदा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद तैयार किया है, ताकि मौजूदा जरूरतों के अनुरूप कानून बनाया जा सके। किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों और पारंपरिक बीजों की सुरक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 और पौध किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम, 2001 के प्रावधान भी मौजूद हैं। मंत्री के अनुसार, बिल में बाजार में बिकने वाली सभी बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण, बीज उत्पादकों, बीज प्रसंस्करण इकाइयों, डीलरों और पौध नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, आपात स्थिति में बीजों की कीमतों को नियंत्रित करने, बीजों के प्रदर्शन की अनिवार्य लेबलिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साथी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बीज विधेयक 2025 अभी पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है और इसे सार्वजनिक किया गया है, ताकि किसान संगठनों सहित सभी हितधारक अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकें। सरकार का कहना है कि यह कानून एक तरफ बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, तो दूसरी तरफ किसानों की परंपरा और अधिकारों की जड़ों को भी मजबूत बनाए रखेगा।

### जाफराबाद में डबल मर्डर, देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग; दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली । दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में देर रात हुई एक सनसनीखेज वारदात में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार, देर रात करीब 1:40 बजे थाना जाफराबाद क्षेत्र में गोली चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान फजील (31 वर्ष) पुत्र अब्दुल, निवासी गली नंबर 30/8, जाफराबाद के रूप में हुई। इस घटना में फजील का भाई नदीम (33 वर्ष) भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों द्वारा उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना जाफराबाद में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो मामले की जांच में सहायक होंगे।

# मथुरा में 8 बसें-3 कारें टकराईं, 13 जिंदा जले

नई दिल्ली ।

कम विजिबिलिटी के कारण मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 127 पर आठ बसों और तीन कारों की टक्कर हो गई, जिसमें तेरह लोगों की मौत हो गई और आग लग गई। 25 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली-आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण हुए एक भयानक चेन एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई और लगभग 75 अन्य घायल हो गए, जब मंगलवार तड़के आठ बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं और उनमें आग लग गई। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के आगरा-नोएडा

- शरीर के टुकड़े 17 पॉलिथीन में ले गए ।
- एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते हादसा, 70 घायल।
- पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया।

कैरिजवे पर हुआ, जहां घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। गाड़ियां एक के बाद एक टकराती गईं, जिससे एक बड़ी आग लग गई जिसने कुछ ही मिनटों में बसों और कारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यात्रियों को बचने का बहुत कम समय मिला। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि सभी गाड़ियों

में लगभग तुरंत आग लग गई, जिससे यात्री अंदर फंस गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही आग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में तेज़ी से फैली, अराजकता का माहौल था। रिपोर्ट के अनुसार, यात्रियों ने बचने की कोशिश की और मदद के लिए चीख-पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस टीमें और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचीं।

दमकलकर्मियों ने आग बुझाई, जबकि बचाव टीमों ने बचे हुए लोगों को बाहर निकाला और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया। लगभग 25 लोगों को इलाज के लिए मथुरा और पड़ोसी जिलों के अस्पतालों में ले जाया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

**पीएम ने PMNRF से मुआवजे का ऐलान किया**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में लोगों की मौत बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 50,000 रुपये मिलेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, राय भर में हवा की क्वालिटी अलग-अलग थी, आगरा में एक्यूआई खराब दर्ज किया गया, जबकि नोएडा गंभीर कैटेगरी में चला गया।

दिल्ली में भी सोमवार सुबह हवा की क्वालिटी गंभीर रही, जहरीली धुंध के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी।

# कैंसर बीमारी-भारत की चुनौतियाँ और नीति सुधार की अनिवार्यत

**वैश्विक** स्तरपर कैंसर आज केवल एक चिकित्सकीय बीमारी नहीं रह गया है,बल्कि यह वैश्विक स्तरपर मानवसभ्यता के लिए एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक औरनीतिगत चुनौती बन चुका हैदुनियाँ के लगभग हर देश में कैंसर मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसे नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज के सबसे खतरनाक रूपों में गिनती है। कैंसर की भयावहता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि यह मानवीय शरीर पर विभिन्न स्वरूपों में हमला करता है कभी फेफड़ों के रूप में, कभी स्तन, सर्वाइकल, प्रोस्टेट, लिवर या रक्त कैंसर के रूप में,और कई बार तब तक पहचान में नहीं आता जब तक यह जीवन के लिए गंभीर खतरा यानी स्टेज फोर या अंतिम समय न बन जाए। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आधुनिक जीवनशैली, पर्यावरणीय प्रदूषण, खानपान में बदलाव, तंबाकू और शराब का बढ़ता सेवन, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता ने कैंसर को एक ऐसी बीमारी बना दिया है जो अब केवल वृद्धावस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि कार्यशील आयु वर्ग को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैवैश्विक रिपोर्टों और स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार, 40 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में कैंसर के मामलों में आने वाले वर्षों में तीव्र वृद्धि की आशंका जताई जा रही है।2030 तक यह आयु वर्गकैंसर के सबसे बड़े जोखिम समूहों में शामिल हो सकता हैयह स्थिति इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि यही वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था,सामाजिक संरचना और पारिवारिकव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यदि इस आयु वर्ग में बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते है, तो इसका प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि उत्पादकता,रोजगार गरीबी, सामाजिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य तक गहराई से महसूस किया जाएगा।यही कारण है कि आज कैंसर से मुकाबला केवल अस्पतालों और डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक नीति,शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन की मांग करता है। साथियों बात अगर हम कैंसर से प्रतिरक्षात्मक उपायों की करें तो जीवनशैली परिवर्तन, कैंसर रोकथाम की पहली सीढ़ी है,कैंसर के बढ़ते मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल इलाज पर आधारित रणनीति पर्याप्त नहीं है। रोकथाम,समय पर जांच और प्रारंभिक निदान ही इस बीमारी से लड़ने के सबसे प्रभावी हथियार है। जीवनशैली में बदलाव जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम,तंबाकू और शराब से दूरी, मानसिक तनाव को नियंत्रित करना और प्रदूषण से बचाव,कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते है। विकसित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं निवारक उपायों पर केंद्रित हैस्कूल स्तर से लेकर कार्यस्थलों तक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाते है, ताकि लोग बीमारी के शुरुआती संकेतों को समझ सकें और समय रहते जांच करा सकें। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां स्वास्थ्य संसाधनों पर पहले से ही भारी दबाव है, जीवनशैली आधारित रोकथाम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।साथियों बात अगर हम भारत में कैंसर- बढ़ता संकट और असमानताएँ इसको समझने की करें तो,भारत में कैंसर की स्थिति वैश्विक रुझानों से अलग नहीं है,बल्कि कई मामलों मे यह और अधिक गंभीर है। जनसंख्या का विशाल आकार, सामाजिक- आर्थिक असमानताएँ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं का अंतर, और जागरूकता की कमी,ये सभी कारक कैंसर के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते है। शहरी क्षेत्रों में जहां निजी अस्पताल और उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कई बार बुनियादी संसाधनों से वंचित रहते है। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रामीण मरीजों में कैंसर का पता अक्सर बहुत देर से चलता है, जब इलाज की संभावनाएं सीमित हो जाती है। इस असमानता का सीधा असर मृत्यु दर पर पड़ता है और यही कारण है कि भारत में कैंसर से होने वाली मौतों का अनुपात कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेपकारी भूमिका, एक ऐतिहासिक मोड़ इसको समझने की करें तो,भारत में कैंसर प्रबंधन की खामियों को उजागर करने में न्यायपालिका की भूमिका हाल के वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह याचिका एम्स के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉ. अनुराग श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिसमें देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में कैंसर प्रबंधन से जुड़ी गंभीर कमियों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया। 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को औपचारिक नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है कि अब इस मुद्दे को केवल नीति-स्तर की चर्चा तक सीमित नहीं रखा जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक कानूनी प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि यदि सरकारें समय रहते ठोस कदम नहीं उठातीं, तो इसका खामियाजा लाखों नागरिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है।न्यायपालिका का यह रुख भारत में स्वास्थ्य अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। साथियों बात अगर हम कैंसर को अधिसूचित बीमारी का दर्जा क्यों है यह इतना जरूरी? इसको समझने की करें की करें तो किसी बीमारी को अधिसूचित घोषित करने का अर्थ यह होता है कि उसके मामलों की रिपोर्टिंग कानूनी रूप से अनिवार्य हो जाती है।अस्पतालों प्रयोगशालाओं और डॉक्टरों को ऐसे मामलों की जानकारी सरकार को देनी होती है,जिससे बीमारी के प्रसार,भौगोलिक वितरण और जोखिम कारकों का सटीक आकलन किया जा सके।

भारत में टीबी, मलेरिया, कोविड-19 जैसी कई बीमारियां अधिसूचित है, जिसके कारण इनके मामलों पर निगरानी और नियंत्रण अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से किया जा सका। कैंसर को अभी तक देशव्यापी स्तर पर अधिसूचित न किया जाना एक गंभीर नीतिगत चूक मानी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 17 ने ही अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। इसका अर्थ यह है कि देश का लगभग आधा हिस्सा अभी भी कैंसर मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग से बाहर है।जब बीमारी के वास्तविक आंकड़े ही सरकार के पास नहीं होंगे, तो प्रभावी नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा? यही वह बुनियादी प्रश्न है जिसने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया। साथियों बात अगर हम आईसीएमआर कैंसर रजिस्ट्री- सीमित कवरेज, सीमित समझ इसको समझने की करें तो, भारत में कैंसर के आंकड़ों का मुख्य स्रोत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा संचालित कैंसर रजिस्ट्री है। लेकिन याचिका के अनुसार, यह रजिस्ट्री फिलहाल देश की केवल लगभग 10 प्रतिशत आबादी को ही कवर करती है। ग्रामीण इलाकों में यह कवरेज मात्र 1 प्रतिशत के आसपास है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश में कैंसर के वास्तविक मामलों का एक बड़ा हिस्सा कभी आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज ही नहीं हो पाता।जब डेटा अधूरा होगा,तो उस पर आधारित रणनीतियां भी अधूरी और अप्रभावी ही होंगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई देशों में कैंसर रजिस्ट्री की कवरेज 80 से 100 प्रतिशत तक है। इन देशों में कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की योजनाएं इसी व्यापक डेटा के आधार पर बनाई जाती है। भारत में डेटा की यह कमी न केवल नीति निर्माण को कमजोर करती है, बल्कि शोध और नवाचार की संभावनाओं को भी सीमित कर देती है। नई दवाओं, उपचार पद्धतियों और रोकथाम कार्यक्रमों के विकास के लिए सटीक और व्यापक आंकड़े अनिवार्य होते है।

साथियों बात अगर हम ग्रामीण भारत और कैंसर एक अदृश्य संकट इसको समझने की करें तो,ग्रामीण भारत में कैंसर की स्थिति को अक्सर अदृश्य संकट कहा जाता है। जागरूकता की कमी,सामाजिक रूढ़ियां,आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव ये सभी कारक मिलकर कैंसर को एक मूक हत्यारा बना देते है। कई बार मरीज शुरुआती लक्षणों को सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते है। जब तक वे किसी बड़े अस्पताल तक पहुंचते है,तब तक बीमारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी होती है। अधिसूचित बीमारी का दर्जा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंसर मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग बेहतर हो सकती है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होगा। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय अनुभव- भारत के लिए सबक इसको समझने की करें तो,अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में देखा है। यूरोप,उत्तरी अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। नियमित मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी और लो-डोज सीटी स्कैन जैसे परीक्षणों को उच्च जोखिम समूहों के लिए अनिवार्य या अत्यधिकप्रोत्साहित किया गया है। इन देशों में कैंसर को अधिसूचित बीमारी के रूप में देखने का लाभ यह हुआ कि नीति निर्माण डेटा- आधारित और लक्ष्य-उन्मुख बन सका।भारत यदि इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेकर कैंसर को देशव्यापी अधिसूचित बीमारी घोषित करता है, तो यह न केवल आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की जवाबदेही भी बढ़ाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा और संसाधनों का आवंटन वास्तविक जरूरतों के अनुसार किया जा सकेगा।

**सम्पादकीय...**

## लापरवाही....

गोवा के बारे में कहा जाता है कि यहां के दिन तो खुशनुमा और मौज-मस्ती से भरे होते ही है, यहां की रातें भी बड़ी रंगीन होती है। मगर चमचमाती रोशनी से नहाए गोवा की रातों का एक स्याह चेहरा भी है, जहां दबंगई है, भ्रष्टाचार है, ड्रग्स का काला कारोबार है और इन सबके बीच बेलगाम घूमते मौत के सौदागर भी है। स्थानीय प्रशासन गांधीजी के तीन बंदरों की तरह है, जिसके बारे में कई लोग सोचते है कि वह सच देखना नहीं चाहता, सच सुनना नहीं चाहता और सच के बारे में कुछ कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गोवा अग्निकांड इसी का नतीजा है। इस अग्निकांड के बारे में बात शुरू करने के पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि पर्यावरण पर ध्यान रखने के लिए हमारे देश में ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है जिसके चेयरमैन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते है। जिस देश में पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां अच्छे पर्यटन की हम कैसे उम्मीद कर सकते है? पर्यटन में वह ताकत होती है कि वह किसी देश की किस्मत बदल दे। स्पेन इसका उदाहरण है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी लेकिन पर्यटन के माध्यम से अपनी आर्थिक सेहत सुधारने में स्पेन कामयाब रहा, मगर भारत में पर्यटन की क्या स्थिति है? मैंने पहले भी अपने कॉलम में लिखा है कि पर्यटक दो तरह के होते है। एक तो अपने देश से आने वाले पर्यटक है और दूसरे है अंतरराष्ट्रीय पर्यटक। बाहर से आने वालों में कुछ पर्यटक ऐसे होते है जिनकी जेब भरी होती है और दूसरे वो होते है जिनकी जेब में बस कामचलाऊ पैसा होता है। दुर्भाग्य से गोवा में कम पैसे वाले पर्यटक ज्यादा होते है। कईयों की जेब में तो लौटने के पैसे तक नहीं होते है, फिर वो हर तरह के धंधे करते है। गोवा में यही हो रहा है। मैंने संसद में भी यह मामला उठाया था लेकिन गोवा में ऐसा नेक्सस है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और कि विदेश में समुद्र तटों के संरक्षण पर खास ध्यान दिया जाता है, वहां के पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करने की इजाजत किसी को नहीं होती लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है? हमने नियम बना दिए कि समुद्र तट के 500 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा लेकिन हमारे यहां इस 500 मीटर के भीतर ही हर तरह के धंधे हो रहे हैं, यहां के कैसिनो पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे है जिससे मरीन लाइफ प्रभावित हो रही है। जलीय जंतुओं में बीमारियां फैल रही है। हमने प्रमाण सहित खबरें भी प्रकाशित की थीं लेकिन स्थानीय शासन के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अवैध रूप से निर्मित जिस नाइट क्लब में आग लगी, वह पणजी से 25 किलोमीटर दूर ऐसे इलाके में है जहां ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी, ऐसे अधकच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है कि राहत पहुंचाने में भी वक्त लग जाए। लोग आग से बचने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे जहां वेंटिलेशन नहीं था। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स से जो चिनगारियां निकलीं उसने लकड़ी की सीलिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जब छतों में लकड़ी की सीलिंग थी तो फिर इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स चलाए ही क्यों गए? और इसके अवैध निर्माण को लेकर 2023 में ही शिकायत हो गई थी. फिर सीवेज नदी में बहाने की शिकायत हुई। जनवरी 2024 में अरपोरा पंचायत ने क्लब का निरीक्षण किया था और अवैध ढांचे के लिए दो महीने बाद मार्च में नोटिस जारी किया। क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। राजस्व अधिकारियों ने नोटिस दिया कि क्लब कृषि भूमि पर बना हुआ है। एक नोटिस कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी दिया लेकिन लूथरा बंधुओं का ऐसा जलवा था कि सारे नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिए। हकीकत यही है कि पूरे देश के राजनीतिक संरक्षण वाले दबंगों के लिए गोवा लूट का अड्डा बना हुआ है। दिल्ली के लूथरा बंधुओं के लिए भी गोवा का उनका नाइट क्लब केवल पैसा कमाने का जरिया था, कोई मरे या जिए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आग की घटना में 25 लोगों की मौत के बाद उनका अमानवीय बर्ताव इसकी गवाही देता है। रात सवा एक बजे उन्हें भीषण अग्निकांड की जानकारी मिली, यदि उनमें मानवीयता होती तो वे मातमपुर्सी के लिए गोवा पहुंचते लेकिन उन्होंने तो थाईलैंड के लिए हवाई टिकट बुक कराया और सुबह 5.30 बजे उड़ चले, बहरहाल, वे अब थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय कानून के दायरे में वे जल्दी लाए जाएंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कैसिनो और नाइट क्लबों का गोरखधंधा, सुरक्षा के प्रति भारी लापरवाही और ड्रग्स का जो खुला खेल गोवा में चल रहा है, उसे कौन रोकेगा? वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति कौन सुधारेगा? 2013 में तब के जाने-माने पत्रकार तरुण तेजपाल द्वारा सहकर्मी के साथ छेड़खानी का मामला तो सामने आ गया था, छेड़खानी के कई मामले बस दबे ही रह जाते है। ड्रग्स ने हालत और खराब की है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्वीकार किया था कि गोवा में ड्रग्स तस्करी होती है। इसी साल अप्रैल में गोवा में 43 करोड़ की कोकीन जब्त की गई। इससे पहले फरवरी में एक जर्मन नागरिक और मार्च में नाइजीरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारियां तो बस छोटा सा हिस्सा है। ध्यान रखिए कि जब किसी इलाके में ड्रग्स का पैसा प्रवाहित होता है तो उसके साथ कई बुराइयां पैदा होती है। आज गोवा में टैक्सी माफिया का बोलबाला है। दक्षिणी गोवा से यदि आपको मनोहर पर्रिकर विमानतल जाना हो तो टैक्सी वाले पांच हजार रुपए मांगते है! क्या सरकार को यह पता नहीं है? चलते-चलते एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा कि कोविड से पहले 2019 में 90 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गोवा आए थे।

## टीएमयू मेडिकल प्रीमियर लीग में एयरवे अवेंजर्स के सिर सजा ताज

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद में टीएमयू मेडिकल प्रीमियर लीग- टीएमपीएल टेनिस बॉल क्रिकेट पहली बार आईपीएल की तर्ज पर हुआ। बोलियां लगी और खिलाड़ी बिके, लेकिन खास बात यह रही कि टीएमपीएल का यह ऑक्शन कर्नुअली रहा। इस नीलामी में ऑलराउंडर शिवा सोलंकी और शान्तनु तोमर सर्वाधिक मंहगे बिके। इन मुकाबलों में मेडिकल स्टुडेंट्स के संग-संग फैकल्टीज ने भी अपना हुनर दिखाया। नौ दिनी इस लीग में पांच टीमों के बीच कुल 14 मैच हुए। टीएमयू के क्रिकेट मैदान पर हुए अंतिम मुकाबले में टीएमयू एयरवे अवेंजर्स की टीम ने टीएमयू टॉक्सिन को आठ विकेट से एकतरफा मात दी। समापन समारोह में तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी की एचओडी प्रो. सीमा अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रो. आरके कौल, डॉ. आरिफ बकार, डॉ. शाहबान आलम, डॉ. असद, डॉ. सुशील कुमार, डॉ. आकाश गांधी आदि मौजूद रहे। टॉस जीतकर एयरवे अवेंजर्स के कप्तान डॉ. अंकुर सिंह ने बॉलिंग चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉक्सिन की टीम निर्धारित 20 ओवर में 167 रनों पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीएमयू एयरवे अवेंजर्स की टीम ने 18 ओवर में ही 02 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एयरवे अवेंजर्स के ऑलराउंडर डॉ. खेलिल देवड़िया ने ×5 बॉल्स पर 42 रन ठोककर 05 विकेट भी चटकाए। इस शानदार प्रदर्शन के बूते डॉ. खेलिल को मैन ऑफ द मैच के संग-संग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। बल्लेबाज डॉ. रजत जून ने सर्वाधिक 48 गेंदों में 82 रनों की जबर्दस्त पारी खेली। डॉ. जून ने अपनी पारी में 06 छक्के और 04 चौके भी जड़े। टीएमयू टॉक्सिन की ओर से डॉ. आमिर शेख की कप्तानी में डॉ. सिमरन सिंह का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। डॉ. सिमरन ने 06 मुकाबलों में 180 रन बनाए और 09 विकेट भी चटकाए। एम्पायर की भूमिका श्री चंद्रशेखर आदि ने निभाई।

## एनसीसी कैडेट्स ने मनाया विजयी दिवस

मुरादाबाद।



23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद की सब यूनिट महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में एनसीसी कैडेटों द्वारा विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने बताया कि आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना के जनरल ए के नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी 93000 सैनिकों ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के आगे आत्म समर्पण कर दिया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उसे एक दिन पहले भारत के दो हिस्से कर दिए गए एक नया देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो हिस्सों में था एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व के द्वारा और सैन्य अधिकारियों के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अपनी दमनकारी नीति चलाई और जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया तो ऑपरेशन सर्च लाइट के अंतर्गत लगभग 20 लाख व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के कारण भारत ने इसकी आवाज उठाई और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान सेना ने जब भारतीय 11 सैन्य ठिकानों पर हमला करा तब भारतीय जल थल वायु सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मात्र 14 दिन में पाकिस्तान सेना को घुटनों पर ला दिया और 93000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे आत्म समर्पण कर दिया इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ऐसा सबक सिखाया पाकिस्तान को की उसके दो टुकड़े कर दिए और नया देश बांग्लादेश बनाया. अमेरिका और चीन ने भी उसी समय भारत के साथ धोखा की और पाकिस्तान के साथ मिल गए लेकिन रूस ने भारत के साथ दोस्ती निभाई और अमेरिका और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज के एनसीसी कैडेट को भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे कर दिहवलदार रंजीत सिंह ने भारतीय सेना की गौरव गाथा इन कैडेटों को बताई उन्होंने कहा कि हाई एल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन की काफी कमी रहती है हमारी सेवा लगातार डटी रहती हैसभी कैडेट इस मौके पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे बोल रहे थेकार्यक्रम के अंत में 1971 युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को एन सी सी कैडेटों द्वारा नमन किया गया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गईइस मौके पर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मेजर राजीव ढल, हवलदार रंजीत सिंह,कार्तिक अग्रवाल,शिवा, हमना वारसी,कृष्णा शर्मा, गरिमा सिंह,खुशबू,करीना सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे।

## जरूरतमंद बच्चों को वितरित किये जर्सी व मोजे



मुरादाबाद।

विकास शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव हेतु आप सबकी रसोई ट्रस्ट परिवार द्वारा गर्म जर्सी एवं मोजों का वितरण किया गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसे 45 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनके पास सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म वस्त्र उपलब्ध नहीं थे। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक एडवोकेट रवि यदुवंशी एवं कमल गोला ने बताया कि ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों की किट वितरित करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेवा करना ही स च्ची समाजसेवा है, क्योंकि यही ब च्चे देश का भविष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था को किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट के सदस्य आपसी सहयोग से समाजसेवा का कार्य करते है। भविष्य में भी किसी मानवीय सेवा की आवश्यकता होने पर ट्रस्ट सदैव अग्रणी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में संस्था महासचिव प्रमोद यादव एवं महिला अध्यक्ष बहन करिश्मा चौहान उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधक विकास सैनी ने की, जिन्होंने संस्था के सदस्यों का स्मृति चिन्ह एवं पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया।

## ऋण संबंधी पत्रावलियों के निस्तारण में देरी पर डीएम सख्त

### बैठक में बैंकर्स की कार्यप्रणाली पर जतायी नाराजगी

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने की स्थिति के बारे में बैंकवार समीक्षा की तथा कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत नियमानुसार प्राथमिकता से ऋण स्वीकृत किया जाए ताकि उन्हें कृषि कार्यों में मदद मिल सके। सीएम युवा योजना में निजी क्षेत्र की बैंकों द्वारा रुचि न लिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा कहा कि निजी एवं राष्ट्रीकृत क्षेत्र की बैंकें विशेष रूचि लेते हुए सरकार की रोजगार परक योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकें अपनी जिम्मेदारी समझें और ऋण-पत्रावली के निस्तारण में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें।उन्होंने ऋण संबंधी पत्रावलियों को निरस्त किए जाने की बैंकवार स्थिति की समीक्षा के दौरान स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि बिना पर्याप्त कारण के आवेदन पत्र किसी भी दशा में निरस्त नहीं होना चाहिए। ऋण स्वीकृति के उपरांत यथाशीघ्र आवेदक को ऋण की धनराशि प्राप्त हो जाए ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें। मत्स्य पालकों के लिए संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में भी बैंकों के स्तर से खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की बैंकवार स्थिति में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा सौर आधारित ऊर्जा स्रोत के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन में बैंक अपनी जिम्मेदारी दिखाएं ताकि आमजन इस योजना के उद्देश्य को समझें और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंइस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।

## शिक्षक हित में मजबूती से काम करने का लिया संकल्प

### राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉ. विशेष कुमार शर्मा बने जिला मंत्री

मुरादाबाद।



राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग की बैठक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद में संपन्न हुई जिसमें सदस्यता एवं संगठन विस्तार करते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ विगत 37 वर्षों से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए लगातार कार्यरत है। आज देश के 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय व तकनीकी शिक्षा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 13लाख 60000 से भी अधिक सक्रिय शिक्षक सदस्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपने गुरु वंदन ,कर्तव्य बोध दिवस ,हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान ,भारत गौरव दिवस आदि कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक उन्नयन एवं पुरातन गुरु शिष्य परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए जन जागरण कर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परम्परा की अवधारणा को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिला अध्यक्ष डॉ राजीव मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं शिक्षकों की गौरव गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए तेज गति से कार्य कर रहा है उन्होंने संगठन विस्तार करते हुए चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद की इकाई में रवेंद्र सिंह को संयोजक ,खुशबू चौधरी एवं विकास त्यागी को सहसंयोजक व उपप्रधानाचार्य वीर सिंह को संरक्षक बनाया। डॉ विशेष कुमार शर्मा को जिला मंत्री एवं जसदेव सिंह जस्सी को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया । बैठक में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मंडल उपाध्यक्ष मेजर सुदेश कुमार भटनागर ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का सदस्य बनने का सभी से आवाहन किया । बैठक में प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ,मंडल उपाध्यक्ष मेजर सुदेश कुमार भटनागर, जिला अध्यक्ष डॉ राजीव मोहन सिंह जिला कोषाध्यक्ष विजय कुमार राम ,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह, अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ राजीव कुमार, उप प्रधानाचार्य वीर सिंह, मेजर शिवकुमार ,नवनीत गोस्वामी आदि दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।

## कोहरे में वाहन ने रौंदी बाइक, युवक की मौत

मुरादाबाद।

मझोला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक अजीत सिंह की मौत हो गई। घने कोहरे के कारण एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अजीत सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिविल लाइंस क्षेत्र के हरथला बड़ा शिव मंदिर निवासी अजीत सिंह सुबह लगभग सात बजे अपनी बाइक से पैपटपुराजा रहे थे। मझोला थाना क्षेत्र के पैपटपुरा पहुंचते ही सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अजीत सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मझोला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने अजीत सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन का चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़क पर दृश्यता बहुत कम थी, जिससे यह हादसा हुआ। मझोला के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने बताया कि फरार वाहन और उसके चालक की जल्द ही पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और मामले की आगे की जांच जारी है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्टलूना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08863)

# 920 लिंगानुपात का लक्ष्य रखें - सुधीर राजपाल

*पिछले साल के मुकाबले 9 अंक सुधरा लिंगानुपात

*कहा, नवजात बच्चों के जन्म पंजीकरण पर फोकस करें

चंडीगढ़ । हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस साल के अंत तक लिंगानुपात 920 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि शहरों एवं कस्बों में माइग्रेटिड पॉपुलेशन वाले एरिया में सभी नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। वे आज यहां लिंगानुपात में सुधार के लिए गठित स्टेट टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर एस ढिल्लो , महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल, निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव, डॉ. कुलदीप सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री सुधीर राजपाल ने कहा कि अधिकारियों की मेहनत की बदौलत प्रदेश के लिंगानुपात में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले साल 15 नवंबर, 2024 को जहां लिंगानुपात का आंकड़ा 907 था, वहीं इस बार 9 अंक के सुधार के साथ आज 916 तक पहुंच गया है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसंबर, 2025 तक लिंगानुपात 920 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्लम क्षेत्रों में नवजात बच्चों का जन्म पंजीकरण कम है, उनमे कैंप लगाकर या लोगों को जागरूक करके जन्म पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की तरफ से उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय पर पहुंचाया जा सके।

# एनसीआर में वायु प्रदूषण के खिलाफ हरियाणा के कड़े कदम

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खेत में पराली प्रबंधन से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, शहरों में धूल नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुपालन तक विभिन्न पहलों की समीक्षा की गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की गई इस समीक्षा बैठक में एक्शन टेकन रिपोर्ट का आकलन करने के साथ-साथ वर्ष 2025-26 के लिए राज्य और शहर स्तरीय कार्य योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, रोहतक और मानेसर सहित एनसीआर के नगर निगमों के लिए शहर-विशिष्ट रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। वर्ष 2018-19 से अब तक 932 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख से अधिक मशीनें किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराई गईं,

जिससे गांवों में धान की पराली का इन-सीटू प्रबंधन संभव हो पाया। छोटे और सीमांत किसानों को समय पर मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की नियमित निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही, एक्स-सीटू उपयोग में भी तेजी आई है और धान की पराली का उपयोग पेलेटाइजेशन यूनिट्स, थर्मल पावर प्लांटों, ईंट भट्ठों और उद्योगों में किया जा रहा है। झज्जर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद और पानीपत में स्थापित कम्प्रैस्ड बायो गैस प्लांट बड़ी मात्रा में पराली का उपयोग कर रहे हैं और कृषि अवशेषों को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित थर्मल पावर प्लांटों ने बायोमास को-फायरिंग में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। नवंबर 2025 तक सभी चालू इकाइयों ने छह प्रतिशत से अधिक बायोमास को-फायरिंग प्राप्त कर ली है। इनमें कम से कम 50 प्रतिशत धान की पराली शामिल है। खेदड़, पानीपत, यमुनानगर और झज्जर के संयंत्रों में बायोमास खपत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। गैर-एनसीआर जिलों में ईंट भट्ठों ने भी अनिवार्य 20 प्रतिशत बायोमास को-फायरिंग शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कार्यक्रम में भी तेजी आई है। विभिन्न खरीद मॉडल्स के तहत 800 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही, पुरानी बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल बसों को एनसीआर जिलों से बाहर स्थानांतरित किया गया है। शहरी धूल नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। एनसीआर शहरों में चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर

## मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मैकेनिकल रोड स्वीपर, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं। प्रमुख सड़कों को पक्का करने और हरित आवरण बढ़ाने के लिए कार्य योजनाएं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भेजी गई हैं। दिसंबर 2025 तक नगर पालिकाओं के 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराने ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

गुरुग्राम में यह लक्ष्य वर्ष 2028 तक निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए प्रस्तावित नए वेस्ट-टू-फ्यूल संयंत्रों से प्रसंस्करण क्षमता की कमी पूरी होगी। निर्माण एवं विखंडन मलबे के प्रसंस्करण की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और रीसाइकल की गई सामग्री का उपयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जा रहा है। बैठक में औद्योगिक अनुपालन की समीक्षा करते हुए दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दैनिक निगरानी, डीजी सेट के रेट्रो फिटमेंट और थर्मल पावर प्लांटों द्वारा उत्सर्जन मानकों के पालन पर जोर दिया गया।

# मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हिसार पहुंचकर अलग-अलग दो स्थानों पर शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री सर्वप्रथम मोहल्ला सैणियान हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय श्री बुद्धराम राड़ा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह सैनी के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने दिवंगत श्री पृथ्वी सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगतों का सामाजिक जीवन प्रेरणादायी रहा है और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा, विधायक श्री रणधीर पनिहार, मेयर श्री प्रवीण पोपली, पूर्व मंत्री डॉ कमल गुप्ता सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।

# केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की पुश्तैनी जमीन पर बनेगी लाइब्रेरी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने किया शिलान्यास

रोहतक ।

रोहतक जिले के गांव बनियानी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पुश्तैनी जमीन पर लाइब्रेरी निर्माण की शुरुआत हो गई है। यह जमीन खट्टर द्वारा पंचायत को दान की गई थी। लाइब्रेरी का शिलान्यास गांव की 92 वर्षीय सबसे बुजुर्ग महिला मूर्ति देवी ने किया। लाइब्रेरी का नाम मनोहर लाल खट्टर की माता शांति देवी के नाम पर रखा जाएगा। मनोहर लाल खट्टर के छोटे भाई चरणजीत खट्टर ने बताया कि 29 जनवरी 2024 को मनोहर लाल ने करीब 200 गज की पुश्तैनी जमीन पंचायत को जनकल्याण के उद्देश्य से सौंप दी थी। इसी जमीन पर अब पंचायत की ओर से लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मूर्ति देवी का शिलान्यास करना भावनात्मक रूप से खास रहा, क्योंकि वे वर्षों तक उनकी माता शांति देवी के साथ काम कर चुकी हैं। चरणजीत खट्टर ने बताया कि लाइब्रेरी परिसर में आधुनिक

सुविधाओं से युक्त ई-लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी, जिससे गांव के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को पढ़ाई और ज्ञान अर्जन का बेहतर अवसर मिलेगा। यह केंद्र भविष्य में शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बता दें कि 2024 में गांव बनियानी पहुंचने पर मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए। उन्होंने कहा था कि उनका बचपन इसी गांव में बीता है और यह भूमि उन्हें अपने माता-पिता की याद दिलाती है, इसलिए इसे गांव के हित में समर्पित किया गया है।

# जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरियाणा गंभीर, वायु प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी नई दिशा

चंडीगढ़ । हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पर्यावरण विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा कर नए शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय है। हरियाणा सरकार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। वायु प्रदूषण को संतुलित करने के लिए विश्व बैंक ने भी पहल की है। इसके तहत हरियाणा को वर्ष 2030 तक लगभग 3000 करोड़ रुपये के सहयोग का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें पहले चरण में वर्ष 2026 तक 1000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। श्री राव नरबीर सिंह ने गत दिनों पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर-दिसंबर के दौरान दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में धुएं की समस्या केवल पराली या मौसमी कारणों से ही नहीं होती, बल्कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, भवन निर्माण कार्य और फैक्ट्रियों का उत्सर्जन भी इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि में ग्रैप-3 व 4 लागू कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, जिसकी अनुपालना एनसीआर से सटे सभी राज्यों द्वारा की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती के लिए अब पेट्रोल पंपों पर स्थापित प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित निरीक्षण पर्यावरण विभाग के अधिकारी करेंगे। साथ ही, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के स्थान पर अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने, जिम्मेदारियां तय करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा व निर्मल जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों के बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता। कृषि प्रधान हरियाणा, विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास की नई पहचान स्थापित करेगा। इसके लिए आगामी पांच वर्षों की एक विस्तृत औद्योगिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किए जाएंगे।

इनमें से दो आईएमटी गुरुग्राम के आसपास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों को हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम अब एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभर चुका है, जहां लघु भारत ही नहीं बल्कि लघु विश्व की झलक देखने को मिलती है। सरकार का उद्देश्य है कि गुरुग्राम औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी आदर्श उदाहरण बने। इसके लिए हरित गुरुग्राम अभियान के तहत बड़े औद्योगिक इकाइयों से सीएसआर फंड के माध्यम से सहयोग लिया जाएगा।

वन विभाग द्वारा गुरुग्राम और सोहना की सभी नर्सरियों को आदर्श हाइटेक नर्सरी के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इन नर्सरियों में ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे, जिन्हें एक-दो वर्ष बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में रोपा जा सके। इसके लिए दक्षिण भारत की आधुनिक नर्सरियों का अध्ययन कर हरियाणा में भी वैसी ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित किया जाएगा।

# संगीता बरुआ बनीं प्रेस क्लब की महिला अध्यक्ष

नई दिल्ली , ( विजय कुमार भारती) प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI ) ने संगीता बरुआ पिशरोटी को अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुना। यह क्लब के जेंडर रिप्रेजेंटेशन और समावेशी नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 13 दिसंबर को हुए चुनावों में बरुआ की टीम ने सभी पदाधिकारियों और प्रबंध समिति के पदों पर 21-0 से शानदार जीत दर्ज की। संगीता ने 1019 वोट हासिल करके निर्णायक जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अतुल मिश्रा और अरुण शर्मा को 129 और 89 वोट मिले।

महासचिव पद के लिए, अफजल इमाम ने 948 वोट हासिल किए और ज्ञान प्रकाश को आसानी से हरा दिया, जिन्हें 290 वोट मिले। जतिन गांधी उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में 1,029 वोट हासिल करके विजयी हुए और प्रतिद्वंद्वी प्रह्लाद सिंह राजपूत को 900 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। अदिति राजपूत (ज्वॉइंट सेक्रेटरी) निर्विरोध चुने गए।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त एमएमसी शर्मा और उनकी टीम ने ढऊक लॉन में पत्रकारों सभा में रिजल्ट का ऐलान किया।

16 सदस्यीय प्रबंध समिति के चुनावों में नीरज कुमार 932 वोटों के साथ सूची में सबसे ऊपर रहे, उसके बाद अभिषेक कुमार सिंह (911), जाह्नवी सेन (903), अशोक कौशिक (892), कल्लोल भट्टाचार्जी (882), प्रवीण जैन (878), अग्रज प्रताप सिंह (865), मनोज शर्मा (861), नयनमा बसु (851), पीबी सुरेश (838), वीपी पांडे (833), प्रेम बहुखंडी (831), मेहा भूरा (829), जावेद अख्तर (823), रेजाउल हसन लस्कर (781) और सुनील कुमार (780) रहे।

परिणाम की घोषणा के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष संगीता ने कहा, यह चुनाव प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों के हमारे पैनल के नजरिये और स्वतंत्र, निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने की हमारी लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता में सामूहिक विश्वास को दर्शाता है। निवर्तमान अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्यों का उनके भरोसे और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नई टीम क्लब को और अधिक समावेशी, जवाबदेह और भारत में पत्रकारों के सामने आने वाली बदलती चुनौतियों के लिए प्रासंगिक बनाने का काम करती रहेगी।

PCI के निवर्तमान महासचिव नीरज ठाकुर ने कहा, 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अपनी स्थापना के बाद से ही देश और विदेश के पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता रहा है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष का चुनाव प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह समानता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति क्लब की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

# लोकसभा में वीबी-जी राम जी बिल पेश

## प्रियंका बोलीं- सरकार को नाम बदलने की सनक; शशूर ने कहा- राम का नाम बदनाम न करो

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे वीबी-जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कमजोर करेगा और इसके तहत दिए जाने वाले 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान को नकार देगा।

लोकसभा में बहस के दौरान वायनाड की सांसद ने कहा कि पर्याप्त परामर्श या चर्चा के बिना किसी भी विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और आरोप लगाया कि यह विधेयक निजी जुनून या पक्षपात के कारण जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि सदन से उचित परामर्श या किसी भी चर्चा के बिना इस विधेयक

को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हालांकि महात्मा गांधी से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, फिर भी वे मेरे परिवार के समान थे। वही पूरे देश की भावना है। इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। किसी भी कानून को केवल व्यक्तिगत जुनून या पूर्वाग्रह के कारण जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ग्रामीण श्रमिकों पर प्रस्तावित कानून के प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नया विधेयक एमजीएनआरईजीए के तहत गारंटीकृत आय के अधिकार को कमजोर करेगा। उन्होंने मौजूदा योजना के तहत मजदूरी भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों को भी उजागर किया। उन्होंने आगे कहा कि नाम बदलने की यह बात मुझे समझ नहीं आती। यह नया विधेयक कम से

### भेदभाव के आधार पर कोई कानून पास नहीं किया जाना चाहिए..., मनरेगा के नाम बदलने पर लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी

कम 100 दिनों के लिए आय के अधिकार को कमजोर कर देगा। आप जहां भी जाएं, एमजीएनआरईजीए कर्मचारी आपको बताएंगे कि उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली है।

इससे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे जी राम जी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, को पेश करने की अनुमति मांगी। इस विधेयक का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।

# 'चुनाव आयोग पर लंबे समय तक रहा एक परिवार का नियंत्रण, कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा; लगाए कई आरोप

नई दिल्ली ।

राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक-एक कर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चुनाव सुधार से लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप तक सभी मामलों में केंद्र सरकार का रुख साफ किया। नड्डा ने वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी जैसे आरोप को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कांग्रेस पर देश को चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चुनाव आयोग का काम एक परिवार द्वारा नियंत्रित पार्टी के जिम्मे रहा, लेकिन उस पर कभी सवाल नहीं उठाए गए।

नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सवाल पूछते हैं कि यह एसआईआर क्यों?, जबकि यह प्रक्रिया नई नहीं है और लोकसभा में 1952 से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चार

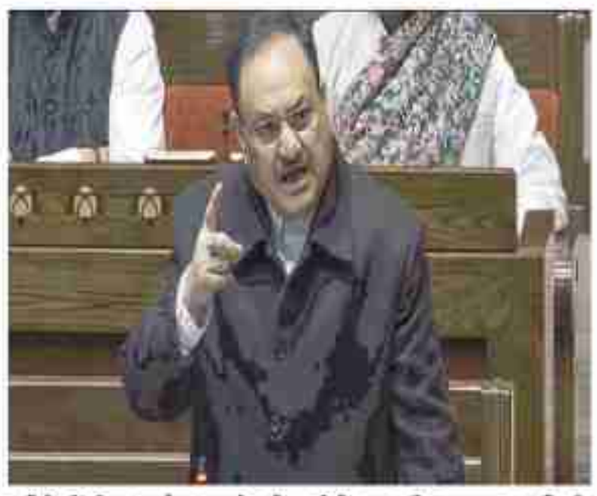

महीनों में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे चुनाव में धांधली हो रही हो। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा से कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में पूरा विश्वास रखती है और हर विषय पर खुले मन से चर्चा के लिए तैयार रहती है। इस दौरान जेपी नड्डा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है कि वह समय-समय पर मतदाता सूची की जांच और सत्यापन कर सके। यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और जरूरी है।

### सदन में चर्चा से पीछे नहीं हटती मोदी सरकार- नड्डा

**चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर दिया जोर**

इस दौरान जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न हो और साथ ही कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रहे। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया की जाती है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि साल 2010 के बाद से मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं हटाया गया है, इसलिए अब इसका पुनरीक्षण और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करेगा।

# सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, गांधी परिवार को कोर्ट से राहत पर बोली कांग्रेस

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी प्राथमिकी की प्रतिलिपि पाने के हकदार नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अपने आधिकारिक एक्स खाते से एक पोस्ट में लिखा, सत्य की जीत हुई है। (नरेंद्र) मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग

इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला धेनाधिकार से बाहर है, उसके पास कोई प्राथमिकी नहीं है जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। पार्टी ने आगे कहा, मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ, राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। धनशोधन का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं, यह सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तर की राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। वहीं, कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा, मैं समझता हूं..एक कहावत है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से यह सत्य की जीत है। मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। कोर्ट ने कहा कि नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय अपनी आगे की जांच जारी रख सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ईडी का मामला किसी प्राथमिकी पर आधारित नहीं है। यह केवल सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दर्ज कराई गई निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है।

# हरियाणा में अब 22 नहीं 23 जिले, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, राज्य को मिला नया जिला

चंडीगढ़ ।

हरियाणा राज्य में अब 22 नहीं 23 जिले होंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23वें जिले का ऐलान हांसी में किया. एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि आज मैं हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं.

सीएम के बयान के बाद जल्दी ही हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी की जाएगी. नया जिला बनने के बाद हिसार जिले में दो तहसीलें हिसार और बरवाला होंगी जबकि हांसी जिले में हांसी और नारनौंद तहसील होंगी. हांसी विकास रैली में सीएम सैनी ने यह ऐलान किया. सीएम ने कहा कि मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं. सीएम के इस ऐलान के बाद ही सभा में मौजूद लोगों ने इसका खुले दिल से

स्वागत किया है. बता दें हांसी को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी कि इसको जिला घोषित किया जाए, दरअसल, हांसी में पुलिस अधीक्षक का दफ्तर पहले से ही है. अब जिले की घोषणा के साथ ही यहां जिला मुख्यालय और जिलाधिकारी का भी दफ्तर होगा. बताया गया कि भिवानी जिलान्तर्गत बवानी खेड़ा के कुछ गांव भी हांसी में शामिल किए जाएंगे. ये गांव एक ओर जहां भिवानी जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वहीं हांसी के जिला बनने से इन ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी जिला कलेक्ट्रेट से सिर्फ 15-17 किलोमीटर रह जाएगी. हांसी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बता दें हांसी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में एक नगर परिषद और विधानसभा क्षेत्र है. यह हिसार से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. हांसी में पुरातात्विक महत्व की कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं वर्ष 2016 में, हरियाणा सरकार ने हिसार जिले से नया हांसी जिला बनाने का प्रस्ताव रखा और 19 अप्रैल ,2017 को पुलिस जिला हांसी अस्तित्व में आया था. हांसी में कई मशहूर ऐतिहासिक जगहें हैं इसमें बरसी गेट, काली देवी मंदिर, जैन और बौद्ध विरासत, पृथ्वीराज चौहान का किला, चार कुतुब शामिल है.

# हिजाब पहनना या न पहनना मुस्लिम महिलाओं का निजी फैसला है, बहस का मुद्दा नहीं- इकरा हसन

शामली। कैराना की सांसद इकरा हसन का हिजाब को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मंगलवार को एक न्यूज चैनल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एंकर ने देश में हिजाब को लेकर चल रही बहस पर सवाल किया। सवाल के जवाब में सांसद इकरा हसन ने साफ कहा कि देश में इससे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार और मीडिया को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हिजाब पहनना या न पहनना किसी महिला की निजी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे ओपन छोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई किसी को हिजाब पहनने या न पहनने के लिए मजबूर करता है, तो वह लोकतंत्र नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह संबंधित महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए और इस पर बार-बार बहस करना ठीक नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों में ऐसे मुद्दों को तूल नहीं दिया जाता, बल्कि असली समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है।

**संस्कृति और परंपरा का भी जिक्र**

सांसद ने कहा, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूं और ऐसे क्षेत्र से आती हूं, जहां सभी समाज की महिलाएं सिर ढकती हैं। यह हमारी संस्कृति है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए।

**अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत**

उन्होंने दो टूक कहा कि समाज और सरकार को शिक्षा, रोजगार, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, न कि पहनावे को राजनीतिक बहस का विषय बनाना चाहिए।

# योगी मंत्रिमंडल विस्तार; यूपी को मिलने जा रहा तीसरा डिप्टी सीएम!

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। इसके साथ ही पार्टी का लंबे समय से रुका हुआ संगठनात्मक बदलाव पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि यूपी की मंत्रिपरिषद में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी केवल 54 मंत्री हैं। यानी अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। इन खाली पदों पर जल्द ही नए चेहरों को जगह मिल सकती है।

**मंत्रिमंडल में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी?**

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। वे पहले योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री

**बता दें कि यूपी की मंत्रिपरिषद में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी केवल 54 मंत्री हैं। यानी अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। इन खाली पदों पर जल्द ही नए चेहरों को जगह मिल सकती है।**

रह चुके हैं। पश्चिमी यूपी में जाट समाज के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी संतुलन साध सकती है। भाजपा सामाजिक संतुलन पर भी ध्यान दे रही है। वर्तमान में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (ओबीसी) और ब्रजेश पाठक (ब्राह्मण) हैं। अब अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से एक नेता को तीसरा डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज है।

**अन्य संभावित मंत्री चेहरे**

सूत्रों के मुताबिक, पूर्व जल शक्ति मंत्री और वर्तमान एमएलसी महेंद्र सिंह की भी मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। वे इस समय मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं।

इसके अलावा, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी छोड़कर आए विधायक मनोज पांडे और बागी सपा विधायक पूजा पाल का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में है।

**कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार?**

सूत्रों के अनुसार, खरमास के बाद यानी जनवरी के आखिर तक कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। भाजपा चाहती है कि आने वाले चुनावी साल से पहले सरकार और संगठन पूरी तरह तालमेल के साथ काम करें।

### बीड में कार और जीप की टक्कर में तीन लोगों की मौत, दो घायल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बीड में आज भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक जीप की कार से टक्कर हो जाने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना सोमवार रात 10.30 बजे अंबाजोगाई-लातूर राजमार्ग पर बरदापुर चौराहे पर हुई। बीड से लातूर जा रही जीप को सामने से आ रही कार से सीधी टक्कर हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए लातूर के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों मृतक लातूर के निवासी थे।